बिसात पर भारतीय लोकतंत्र...

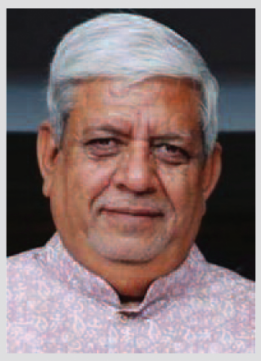

राकेश अचल

ठारहवीं लोकसभा के लिए चुनाव सात चरणों में होना है। होना ही चाहिए। हमारे यहाँ सात भांवरों का,सात-पांच वचनों का बड़ा महत्व है। हमारे खगोल शास्त्र में भी सप्तऋषियों का उल्लेख मिलता है ।हम सात जन्मों और सात समंदरों में यकीन करने वाले लोग हैं। ,इसलिए मतदान भी सात चरणों में हो तो कोई आपत्ति नहीं करना चाहिये । आखिर केंचुआ को भी तो किसी न किसी को उपकृत करना होता है। इत्ता बड़ा देश है यदि एक-दो चरण में नयी सरकार चुन लेगा तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को कहने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए ,फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे।

भारत का लोकतंत्र अठारहवीं बार बिसात पर है । लोकतंत्र को जीतने के लिए बाजियां लग रहीं है। कोई जान की बाजी लगा रहा है तो कोई ईमान की बाजी लगा रहा है । किसी ने आँखें खोलकर बाजी लगाने की तैयारी की है तो कोई आँखें बंद कर ब्लाइंड खेलने पर आमादा है। सबकी अपनी-अपनी तैयारी है । किसी ने 2024 के लिए दांव लगाने का इंतजाम किया है और किसी की नजर 2047 पर है। यानि एक से बढ़कर एक योद्धा मैदान में हैं और बेचारे मतदाता की जान सांसत में है। लगता है जैसे वो खुद मोहरा है। सभी मिलजुलकर उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

भारत में चुनाव कोई नयी बात नहीं है । जब भारत आजाद नहीं था तब भी उसने चुनाव देखे हैं और आजाद होने के बाद से लगातार भारत और भारत का जनमानस चुनावों से गुजरता हुआ ही 1947 से 2024 तक आ पहुंचा है। चुनाव कराने के लिए भारत के पास एक केंद्रीय चुनाव आयोग है। इस आयोग को चुनाव लड़ने वाले और चुनाव में मोहरा बनने वाले लोग प्यार से केंचुआ कहते हैं,लेकिन मै ठहरा साहित्य का विद्यार्थी ,इसलिए मै चुनाव आयोग को केंचुआ नहीं बल्कि भूमिनाग कहता हूँ । रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने भी केंचुए को भूमिनाग कहकर ही इज्जत बक्शी है।

आप केंचुआ को दंतहीन,नखहीन या विषहीन कहें लेकिन केंचुआ है कि पूरे पांच साल चुनावों की तैयारी करता है । ये तैयारी युद्धस्तर की होती है और हर चुनाव के बाद नया चुनाव केंचुआ के लिए एक बड़ी चुनौती होता है,क्योंकि हर चुनाव में मतदाताओं की संख्या में घट-बढ़ होती रहती है। देश की विविधता तथा संस्कृति ही नहीं बल्कि भूगोल भी केंचुआ की तैयारियों को प्रभावित करता है। मतदान कराने के लिए मतदाताओं तक चुनाव लड़ने वाले पहुंचे या न पहुंचें लेकिन केंचुआ वहां तक पहुंचता है । इसलिए केंचुआ तमाम निन्दा और आलोचनाओं के बावजूद प्रशंसा का पात्र भी है। केंचुआ पहाड़,जंगल,नदी-नाले,सर्दी,गर्मी,बरसात की तमाम बाधाओं को पार करने में सिद्धहस्त हो चुका है। समय के साथ केंचुआ की महारत भी लगातार बढ़ी है।

देश में अठारहवीं बार संसद के लिए चुनाव करने जा रहे केंचुआ ने इस बार लगभग 97 करोड़ मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल कराने के लिए इंतजाम किये हैं ताकि झंझावातों में फंसा लोकतंत्र महफूज रह सके ,उसका फ्यूज न उड़े। लोकतंत्र का फ्यूज उड़ाने की हालिया

कोशिशों से सारा देश और दुनिया वाकिफ है ,इसलिए इस पर विस्तार से फिर कभी। केंचुआ ने 18 साल के नवोदित मतदाता से लेकर शतायु हो चुके मतदाताओं की भी चिंता की है। देश का सौभाग्य है कि उसके पास आज भी दो लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पूरी शताब्दी देखी है । केंचुआ ने इस बार 85 साल की उम्र पार कर चुके मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की व्यवस्था भी की है ,यदि वे चाहें तो। केंचुआ वृहन्नलाओं की भी बराबर फिक्र करता है।

भारतीय लोकतंत्र में हर तरह का बल इस्तेमाल किया जाता है । केंचुआ के पास चुनाव के लिए डेढ़ करोड़ कर्मचारी और लाखों का फौज-फांटा होता है। केंचुआ के समाने केवल गौधन,गजधन,बाजधन और रतनधनों से निबटने की ही चुनौती नहीं होती बल्कि उसे इलेक्टोरल धन और बाहुबल से भी निबटना पड़ता है। हर किसी की कोशिश होती है कि वो लोकतंत्र की डोली बलात अपने घर ले जाये। कभी इसमें कामयाबियां भी मिलती हैं और कभी नहीं भी। बलाबल के इस्तेमाल से जब-तब चुनाव रक्तरंजित भी हो जाते हैं ,लेकिन केंचुआ का कहना है की वो चुनावों में किसी भी सूरत में रक्तपात नहीं होने देगा । मेरा मन करता है कि इस आश्वासन के लिए मै केंचुआ के मुंह में घी-शक्कर भर दूँ।

खुशी की बात है कि केंचुआ सियासत में बढ़ती अदावतों और घटियापन से भी वाकिफ है। लेकिन ये सिर्फ खुशी की बात है संतुष्ट होने की बात नहीं, क्योंकि सियासत के घटियापन से निबटने के लिए केंचुआ घटियापन कहाँ से लाएगा ? केवल एडवांस एडवाइजरी जारी करने से तो बात बनने वाली नहीं है । इसके लिए एक्शन की भी जरूरत है जो शायद केंचुए के बूते की बात नहीं है ,क्योंकि आखिर केंचुए को झुकना तो अपने नियोक्ता के प्रति ही है। हालाँकि केंचुआ नियोक्ता के प्रति नहीं बल्कि संविधान के प्रति जबाबदेह है। केंचुआ भी इस हकीकत से वाकिफ है लेकिन उसकी अपनी मजबूरियां भी हैं। जैसे सभी को राम कठपुतलियों की तरह नाचते हैं ,उसी तरह केंचुए को भी नचाने वाले/ नथने वाले तमाम सपेरे देश की सियासत में मौजूद हैं। [खुदा खैर करे]

चुनाव गोया की एक पर्व है इसलिए उसे पर्व की ही तरह मनाया जाना चाहिए न कि महाभारत की तरह और न कि किसी जुए की तरह खेला जाना चाहिए। पर्व में होम-हवन सब होता है। चुनाव में भी बहुत सा जनधन और मानवश्रम का होम-हवन होगा इसलिए जरूरी है कि इस पर्व में सभी पक्ष एहतियात बरते । हम लिखने वालों की यही एडवाइजरी है । इससे ज्यादा हम लोग कर भी क्या कर सकते हैं ? केंचुआ भी तो हमारी ही तरह कभी कुछ नहीं कर पाता। देश का दुर्भाग्य ये है कि देश का बुद्धिजीवी समाज भी केंचुए की तरह अपवादों को छोड़कर नख-दन्त विहीन हो चुका है। अपने-अपने बिल में घुसा हुआ है। एक दशक की अराजकता /रामराज के बावजूद 1975 की तरह समग्र क्रांति का बिगुल नहीं फूंक पाया है। समस्या ये है कि देश बार-बार जयप्रकाश नारायण कहाँ से लाये। देश को इंदिरा मैया और मोदी भैया तो बार-बार मिल जाते हैं।

देश को इस चुनाव के जरिये 2047 के लिए नहीं 2029 तक के लिए ही सरकार को चुनना है। 2047 तक तो उसे बार बार सरकार चुनने का मौका मिलेगा ,इसलिए दूर की न सोचें ,पास की ही सोचे। देश में पहले भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर काम होता रहा है ,23 वर्षीय योजनाएं दुनिया के किसी भी देश में न बनाई जाती हैं और न उनके ऊपर काम हो पाता है ,उलटे इस कोशिश में घल्लूघारा हो जाता है। इससे बचने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा सोचना और करना हमेशा लाभदायक नहीं होता। वैसे दूर-दृष्टि और पक्का इरादा कांग्रेस का पुराना नारा रहा है और गारंटी भी कोई नया शब्द नहीं है । कांग्रेस ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में गारंटी बहुत पहलेबाबस्ता कर दी थी । फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की गारंटी महात्मा गाँधी के नाम से थी और भाजपा की गारंटी महात्मा मोदी जी के नाम से है।

बहरहाल अठारहवीं लोकसभा के लिए चुनाव सात चरणों में होना है। होना ही चाहिए। हमारे यहाँ सात भांवरों का,सात-पांच वचनों का बड़ा महत्व है। हमारे खगोल शास्त्र में भी सप्तऋषियों का उल्लेख मिलता है ।हम सात जन्मों और सात समंदरों में यकीन करने वाले लोग हैं। ,इसलिए मतदान भी सात चरणों में हो तो कोई आपत्ति नहीं करना चाहिये । आखिर केंचुआ को भी तो किसी न किसी को उपकृत करना होता है। इत्ता बड़ा देश है यदि एक-दो चरण में नयी सरकार चुन लेगा तो लोग क्या कहेंगे ? लोगों को कहने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए ,फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोडो बेकार की बातों को ,कहीं बीत न जाये महीना । आखरी बात ये है कि इस चुनाव में फिलहाल वन नेशन,वन इलेक्शन का सपना तो पूरा नहीं हो रहा किन्तु सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल, आंध्र जैसे अनेक राज्य हैं जहाँ की जनता वन नेशन,वन इलेक्शन का प्रतीकात्मक आनद ले सकती है सांसदों के साथ ही अपने विधायक चुनकर। अब ये उन राज्यों की जनता पर निर्भर करता है की वे अपने लिए सिंगल इंजिन की सरकार चुनें या डबल इंजन की। बहरहाल मेरी और से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ,भले ही वे चुनाव लड़ रहे हों,या लड़ा रहे हो। या मूकदर्शक बनकर लोगों को चुनाव लड़ते-लड़ाते देख रहे हों।

संपादकीय

भाजपा के सहयोगियों को खास सुरक्षा

भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने खुले हाथ से सुरक्षा बांटी है। देश के हर हिस्से में बड़ी संख्या में ऐसे नेता मिल जाएंगे, जिनको वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। अगर नेता भाजपा की सहयोगी पार्टी का है तो उसको सुरक्षा मिलने की संभावन ज्यादा रहती है। भाजपा के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोगियों को अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा मिली हुई है। भाजपा ने अपने नेताओं को भी सुरक्षा देकर उनका कद बढ़ाया है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद तो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जीते अपने सभी 75 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा मुहैया करा दी थी। इसी तरह महाराष्ट्र में शिव सेना और एनसीपी टूटने के बाद कई नेताओं को सुरक्षा दी गई। हाल में दो नेताओं को मिली सुरक्षा चर्चा का विषय है। भाजपा की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सुरक्षा उनको पहले से मिली थी लेकिन उसे अपग्रेड किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वे दो की बजाय तीन सीट मांग रही थीं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के भतीजे आकाश आनंद को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। पिछले ही दिनों मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है और साथ ही विपक्ष की पार्टियों के साथ तालमेल नहीं करने का ऐलान भी किया।

विवादित नेताओं की फिर कटी टिकट

भाजपा में विवादित नेताओं की टिकट कटने का सिलसिला जारी है। पार्टी ने पहली सूची में कई विवादित नेताओं को बेटिकट किया है। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रही भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो संसद के अंदर बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित बयान देने वाले रमेश विधूड़ी को भी टिकट नहीं मिली। यह सिलसिला दूसरी सूची में भी जारी रही। भाजपा ने 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में कर्नाटक के दो ऐसे सांसदों की टिकट काटी है, जो पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी कारण से विवादों में घिरे रहे थे और उनकी वजह से पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा। भाजपा ने इस बार कर्नाटक से अपने सांसद प्रताप सिम्हा की टिकट काट दी। पिछले दिनों वे इस बात को लेकर विवाद में आए थे कि उनकी सिफारिश पर कुछ लोगों का सांसद का पास बना था, जिन्होंने संसद भवन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। दो लोगों ने तो संसद की दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर छलांग लगा दी थी और धुआं छोड़ा था। बाद में इनको गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इस सिलसिले में प्रताप सिम्हा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीत कर संविधान बदलने का बयान देने वाले भाजपा सांसद अनंद हेगड़े की टिकट भी कट गई है।

चिंतन-मनन

नित अभ्यास से दर्शन कर सकते हैं ईश्वर का

सभी शास्त्र कहते हैं कि बिना भगवान को प्राप्त किये मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए भगवान की तलाश के लिए कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद, कोई गुरूद्वारा, तो कोई गिरजाघर। लेकिन इन सभी स्थानों में जड़ स्वरूप भगवान होता है। अर्थात ऐसा भगवान होता है जिसमें कोई चेतना नहीं होती है। असल में भगवान की चेतना तो अपने भक्तों के साथ रहती है इसलिए मंदिर में हम जिस भगवान को देखते हैं वह मौन होकर एक ही अवस्था में दिखता है। जब हमारी चेतना यानी इन्द्रियां अपने आस-पास ईश्वर को महसूस करने लगती है तब हम जहां भी होते हैं वहीं ईश्वर प्रकट दिखाई देता है। उस समय भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर या किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब व्यक्ति के साथ चल रही भगवान की चेतना व्यक्ति के मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर में मौजूद ईश्वर की प्रतिमा में समा जाती है और मूक बैठी मूर्ति बोलने लगती है। यह उसी प्रकार होता है जैसे मृत शरीर में आत्मा के प्रवेश करने पर शरीर में हलचल होने लगती है। शरीर की क्रियाएं शुरू हो जाती है।?

मंदिर में विराजमान मूर्ति वास्तव में एक मृत शरीर के समान है। मृत की पूजा करें अथवा न करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति वही कर सकता है जिसमें चेतना हो प्राण हो। इसलिए तीर्थों में भटकने की बजाय जिस देवता की उपासना करनी हो उसे अपनी आत्मा से ध्यान करें उनकी आत्मा अर्थात परमात्मा से संपर्क करें, परमात्मा की पूजा करें तो, जो फल वर्षों मंदिर यात्रा से नहीं मिल सकता, वही फल कुछ पल के ध्यान से मिल सकता है।

अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ जांच शुरू

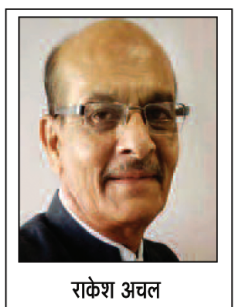

राकेश अचल

अमेरिका में गौतम अडानी और अडानी समूह के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस और वाशिंगटन न्याय विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में टिप्पणी करने से मना कर दिया है। अमेरिका का कानून, अपने अधिकारियों को विदेश में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में क्रास एग्जामिनेशन और दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति देता है। अमेरिकी कानून के अनुसार इस तरह की किसी भी जांच के लिए एक शर्त होती है। अमेरिका के निवेशक का पैसा यदि उसमें लगा हुआ है, तो इस तरह के मामले में जांच की जा सकती है। 24 जनवरी 2023 को हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर मनी लांड्रिंग के जरिए शेयर मैनिपुलेशन करने के आरोप लगाए गए थे। केस की जांच अमेरिका में अब शुरू हुई है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ने 16 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने के लिए कहा था। सेबी ने एक हिसाब से अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला लगभग ठंडे बस्ते में चला गया है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, रिन्यूबल एनर्जी कंपनी, एज्योर पावर ग्लोबल की जांच की जा रही है। न्यूयॉर्क के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस और वाशिंगटन के न्याय विभाग द्वारा धोखाधड़ी की जांच की जा रही है।

भारत में हाल ही में इलेक्टोरल बांड का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तूल पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बांड के संबंध में समस्त जानकारी स्टेट बैंक आफ इंडिया को चुनाव आयोग को देनी पड़ी है। चुनाव आयोग ने स्टेट बैंक से मिली जानकारी को पोर्टल में अपलोड कर दिया है। उसके बाद से ही भारत में कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार, ईडी और सीबीआई की संलिप्तिता को लेकर तूफान मचा हुआ है। इलेक्टोरल बांड भारत का अभी तक का हुआ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला बताया जा रहा है। विपक्षी दलों द्वारा इस मामले में अडानी समूह के साथ-साथ सरकार को भी निशाने पर लिया गया है। भारत सरकार की अडानी समूह पर मेहरबानी रही है। इलेक्टोरल बांड के साथ-साथ अब पीएम केयर फंड के घपले-घोटाले में शामिल किया जा रहा है। जिस तरह से इलेक्टोरल बांड की जानकारी को गुप्त रखा गया था, उसी तरह पीएम केयर फंड की जानकारी को भी गुप्त रखा गया है। सूचना अधिकार कानून के तहत इसकी कोई जानकारी अभी तक उजागर नहीं की गई है। पीएम केयर फंड का कोई भी ऑडिट केग तथा सीएए द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। भारत में इलेक्टोरल बांड के खुलासे के बाद अब पीएम केयर फंड को भी विपक्ष ने निशाने पर ले लिया है।

अमेरिका में गौतम अडानी के आचरण तथा अडानी समूह की कंपनी द्वारा भारतीय अधिकारियों को एनर्जी प्रोजेक्ट में अपने मन मुताबिक काम करने के लिए रिश्वत देने का आरोप है। अमेरिकी न्यायालय तथा कानून विभाग की जांच में अडानी समूह को सारी जानकारी अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। अमेरिकी न्यायालयों और जांच एजेंसी का काम करने का तरीका भारत से अलग है। भारत में अडानी समूह के बचाव में सरकार खड़ी हो गई थी। अमेरिका में यह संभव नही हो पाएगा। भारत में रिलायंस समूह और अडानी समूह के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा भी अमेरिकी जांच को नया मोड़ दे सकती है। अडानी समूह का अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। उसके अंतरराष्ट्रीय निवेशक हैं। हिन्डबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह के ऊपर मनी लांड्रिंग और शेयर मैनिपुलेशन के आरोप हैं। उनकी जांच शुरू हो जाने से भविष्य में अडानी समूह की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। अडानी समूह द्वारा अमेरिका में इस तरह की जांच से इनकार किया है, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार अमेरिका में जांच शुरू हो गई है। भारत के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है, अमेरिका में अडानी समूह का बच पाना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद के चुनाव इसी वर्ष होना है। अमेरिका का मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस तरह की खबरों को उजागर करने में जी-जान लगा देता है। ऐसा लगता है कि अब अडानी समूह की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं।

वैश्विकी: चुनाव का मौसम और अमेरिका

दिलीप चौबे

भारत में आम चुनाव को लेकर दुनिया भर में दिलचस्पी है, हालांकि अधिकतर राजधानियों में यह विश्वास है कि राजनीतिक निरंतरता कायम रहेगी। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विदेश दौरों और कूटनीतिक आयोजनों की तारीख पहले से तय हो रहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सभी देश प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में वापसी की संभावना से खुश हैं, लेकिन उन्हें हकीकत से समझौता करना पड़. रहा है। अमेरिका जैसे देश खुफिया एजेंसियों सहित विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी जुटाते हैं कि हवा का रुोख क्या है। लेकिन अब इन देशों के पास ऐसी ताकत और सामर्थ्य नहीं है कि वे चुनावी राजनीति को पहले की तरह प्रभावित कर सकें। उन्हें इस बात की भी आशंका रहती है कि चुनावी नतीजे उनकी आशा के अनुरूप नहीं रहे तो नई सरकार उनके प्रति कैसा रवैया अपनाएगी।

अमेरिका ने आम चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे भारत के कुछ कूटनीतिक तबके आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। नए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया ऐसा ही एक उदाहरण है। सीएए पर अमेरिका का बयान बहुत सधा हुआ है तथा इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई ऐसी बात न बोली जाए जिससे भारत में किसी को आपत्ति हो। बावजूद इसके स्पष्ट है कि अमेरिका सीएए को भेदभावपूर्ण और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के खिलाफ मानता है। भारत ने बाइडन प्रशासन की आपत्ति को खारिज कर दिया।

नवीनतम घटनाक्रम में अमेरिका से यह रिपोर्ट आई थी कि वहां का जस्टिस विभाग भारत के उद्योगपति गौतम अदानी के विरुद्ध जांच कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अदानी पर यह आरोप है कि उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सौदे हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी। आश्चर्य की बात यह है कि यदि पूरा मामला भारत में हुए सौदों और भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का है तो अमेरिका इसमें टांग क्यों अड़ा रहा है। भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस दौरान अमेरिका की ओर से यदि कोई खुलासा किया गया तो इसे चुनाव में सीधा हस्तक्षेप माना जाएगा। नई सरकार अमेरिका की ऐसी किसी कार्रवाई पर निश्चित रूप से सख्त रवैया अपनाएगी।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल में एक साक्षात्कार में कहा कि अर्थव्यवस्था की तरह राजनीति भी ग्लोबल हो गई है। उनकी मुख्य चिंता यह है कि जो राजनीतिक तबके घरेलू राजनीति में असफल हो जाते हैं वे अन्य देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। विदेशी मीड़िया और थिंक टैंक के जरिये भारत में लोकतंत्र की सेहत के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। इस सिलसिले में जयशंकर का वह बयान उल्लेखनीय है कि उन्होंने अमेरिकी पूंजीपति जॉर्ज सोरोस को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि सोरोस एक बुजुर्ग और निश्चित मत वाले धन पशु हैं। आमतौर पर उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब धन-बल के जरिये किसी देश में जनमत निर्माण की कवायद करता है तो यह चिंता की बात है। इस संबंध में रूस में राष्ट्रपति चुनाव को एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा सकता है। रूस में मतदान जारी है तथा राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन की विजय निश्चित है।

यूक्रेन युद्ध में रूस के हाथों मात खाने वाला अमेरिका पुतिन की जीत को रोकने की स्थिति में नहीं है। केवल 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका ने पुतिन के सामने गंभीर चुनौती पेश की थी। उस समय रूस का राष्ट्रवादी तबका पुतिन के पक्ष में लामबंद हो गया था। इसे समय का फेर कहा जाएगा कि अब अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर आरोप लगाते हैं कि वह उनके यहां चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

अमेरिका में 2016 के चुनाव में ड़ोनाल्ड़ ट्रंप की जीत को पुतिन की साजिश का नतीजा बताया गया था। इसी तरह यूरोप के कई देशों के नेता भी अपनी संभावित हार का दोष पुतिन पर मढ़ने की कवायद कर रहे हैं। देर-सबेर उन नेताओं को यह सचाई स्वीकारनी होगी कि यूक्रेन और गाजा के संबंध में उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं, उन्हें जनता पसंद नहीं करती। बुद्धिमानी तो यह होगी कि ये नेता अपनी नीतियों में बदलाव करें तथा रूस को कोसना बंद करें।